परियोजना संख्या: 53277-002
अप्रैल 2021

भारत: असम कौशल विश्वविद्यालय परियोजना

असम सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक के लिए तैयार किया गया

यह स्वदेशी लोगों की योजना उधारकर्ता का एक दस्तावेज है। यहां व्यक्त किए गए विचार अनिवार्य रूप से एडीबी के निदेशक मंडल, प्रबंधन, या कर्मचारियों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और प्रकृति में प्रारंभिक हो सकते हैं।

किसी भी देश के कार्यक्रम या रणनीति को तैयार करने में, किसी भी परियोजना के वित्तपोषण में, या इस दस्तावेज़ में किसी विशेष क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र का कोई पदनाम या संदर्भ लेकर, एशियाई विकास बैंक का कानूनी या किसी क्षेत्र की अन्य स्थिति के बारे में कोई निर्णय लेने का इरादा नहीं है।

मुद्रा समकक्ष

(26 मार्च 2021 के रूप में)

मुद्रा इकाई	-	भारतीय रुपया / s (₹)
₹ 1.00	=	$ 0.0137
$ 1.00	=	₹ 72.62

संकेताक्षर

एडीबी	-	एशियाई विकास बैंक
एसडीएम	-	असम कौशल विकास मिशन
एएसयू	-	असम कौशल विश्वविद्यालय
जीईआर	-	सकल नामांकन अनुपात
जीआरसी	-	शिकायत निवारण समिति
जीआरएम	-	शिकायत निवारण तंत्र
आईपीपी	-	स्वदेशी लोग योजना
आईटीआई	-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईएनआरएम	-	भारत निवासी मिशन
पीएमयू	-	परियोजना प्रबंधन इकाई
पीएससी	-	परियोजना संचालन समिति
आर & डी	-	अनुसंधान और विकास
एसईईडी	-	कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग
एसपीएस	-	सुरक्षा नीति वक्तव्य
टीवीईटी	-	तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण

टिप्पणियाँ

(i) भारत सरकार और उसकी एजेंसियों का वित्तीय वर्ष (FY) 31 मार्च को समाप्त होता है। कैलेंडर वर्ष से पहले "FY" उस वर्ष को दर्शाता है जिसमें वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, उदाहरण के लिए, FY 2021 31 मार्च 2021 को समाप्त होता है।

(ii) इस रिपोर्ट में, "$" संयुक्त राज्य डॉलर को संदर्भित करता है।

सामग्री

I. **परिचय** 1

II। **परियोजना** 1

ए **पृष्ठभूमि** 1

बी **परियोजना विवरण** 4

III। **असम में स्वदेशी लोगों का अवलोकन** 5

IV. **सामाजिक प्रभाव आकलन** 8

वी. **सूचना प्रकटीकरण, परामर्श, और भागीदारी** 10

VI. **स्वदेशी लोगों के लिए कार्य योजना** 12

VII. **शिकायत निवारण तंत्र** 13

VIII. **निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन** 15

IX. **संस्थागत व्यवस्थाएं** 15

X. **बजट और वित्त पोषण** 15

नंबर 19
हितधारकों से परामर्श 19
दिनांक 19
1. 19
सुश्री मधुचंदा तालुकदार, असम सिविल सेवा (एसीएस) 19
11 नवंबर 2021 19
2 19
श्री मृगेश एन बरुआ, एसीएस 19
11 नवंबर 2020 19
3 19
सुश्री शांता शर्मा 19
11 नवंबर 2020 19
4 19
दरांग जिले में परामर्श बैठक 19
श्री दिलीप कुमार बरुआ 19
12 नवंबर 2020 19
5 19
मंगलदोई में एएसयू परिसर स्थल के आसपास 14 निवासियों (8 महिलाएं, 6 पुरुष) के साथ परामर्श बैठक 19
12 नवंबर 2020 19
6 19
40 छात्रों (10 महिलाएं, 30 पुरुष) और 10 प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी (8 महिलाएं, 2 पुरुष), के साथ समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित करें। अजिताक्ष वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 19
11 नवंबर 2020 19
7 19

5 प्रशिक्षक (4 महिलाएं, 1 पुरुष) और 20 छात्र (12 महिलाएं, 8 पुरुष), के साथ समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित करें। फ्लाईवे प्रशिक्षण संस्थान 19
21 जनवरी 2021 19
8 19
15 छात्रों (10 महिलाएं, 5 पुरुष) और 10 प्रशिक्षकों (7 महिलाएं, 3 पुरुष), के साथ समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित करें। नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर, गुवाहाटी 19
21 जनवरी 2021 19
9 19
21 जनवरी 2021 19

अनुबंध 1: हितधारक परामर्श 18

अनुबंध 2: हितधारक परामर्श का विवरण 20

I. परिचय

1. यह प्रारूप गरीबी, सामाजिक, लिंग और स्वदेशी लोगों के आधार पर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सुरक्षा नीति वक्तव्य (एसपीएस 2009) की आवश्यकताओं के अनुसार भारत में प्रस्तावित असम कौशल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए स्वदेशी लोगों की योजना (आईपीपी) का मसौदा तैयार किया गया है। लोगों का मूल्यांकन परियोजना की तैयारी के हिस्से के रूप में उचित परिश्रम और हितधारक परामर्श के रूप में किया जाता है।

2. भारत सरकार ने परियोजना को वित्तपोषित करने में मदद करने के लिए एडीबी के सामान्य पूंजी संसाधनों से 112 मिलियन डॉलर के नियमित ऋण का अनुरोध किया है। यह परियोजना सभी के लिए अच्छा रोजगार सुनिश्चित करने और टिकाऊ और समावेशी बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए अपनी कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत करने में असम सरकार की सहायता करेगी। यह एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) और उच्च शिक्षा के बीच कौशल प्रगति और गतिशीलता के लिए मार्ग तैयार करेगा जो उच्च शिक्षा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास (आर & डी) के साथ एकीकृत कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण अंतराल को भर देगा। और उद्यमिता शिक्षा और समर्थन, और असम और अन्य राज्यों में उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कौशल स्तर बढ़ाएगा। यह परियोजना युवाओं और वयस्कों, विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समूहों के लोगों के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी और उच्च-भुगतान वाली, अच्छी नौकरी पाने की उनकी संभावना में सुधार करेगी।

3. असम सरकार कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग (SEED) निष्पादन एजेंसी होगी, और असम कौशल विकास मिशन (ASDM) कार्यान्वयन एजेंसी होगी। SEED परियोजना गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक परियोजना संचालन समिति की स्थापना करेगा। ASDM ने एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना की है, जो परियोजना के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।

4. 2011 की जनगणना के अनुसार असम 3.88 मिलियन अनुसूचित जनजाति के लोगों का घर था, जिनकी कुल आबादी (2011 की जनगणना) का 12.4% हिस्सा था। परियोजना से अनुसूचित जनजाति की आबादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि उन्हें लाभ होगा। अनुसूचित जनजाति समूहों के युवाओं और वयस्कों की उद्योग-संबद्ध कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच होगी, जो उच्च-भुगतान वाली, अच्छी नौकरी पाने की उनकी संभावना को बढ़ाएगा। परियोजना को स्वदेशी लोगों के लिए (बी) श्रेणीबद्ध किया गया है और यह आईपीपी अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए कौशल शिक्षा और

प्रशिक्षण, कैरियर विकास कार्यक्रमों और सेवाओं तक पहुंच में सुधार के उपायों के साथ तैयार किया गया है।

II. परियोजना

A. पृष्ठभूमि

5. असम, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों के लिए एक रणनीतिक स्थिति रखता है।[1] अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और शेष भारत की तुलना में युवा आबादी (40 वर्ष से कम आयु) के उच्च अनुपात के बावजूद, असम ने अभी तक अपनी विकास क्षमता को उजागर नहीं किया है। लैंडलॉक होने के कारण, बड़े पैमाने पर ग्रामीण, और अविकसित बुनियादी ढांचे के साथ, असम की अर्थव्यवस्था कम मूल्य वर्धित, प्राकृतिक संसाधन-आधारित उत्पादों का प्रभुत्व है और क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ खराब रूप से एकीकृत है। इसके विनिर्माण क्षेत्र आउटपुट और पूंजी निवेश के मामले में विविध और छोटे हैं। एडीबी द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आक्रामक बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास, विशेष रूप से, गलियारा आधारित औद्योगिक विकास, असम के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए आवश्यक है। फिर भी कुशल कार्यबल की सीमित उपलब्धता को इस रणनीति की बाधाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है।[2]

[1] उदाहरण के लिए, दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी), बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहल (बीआईएमएसईसी), और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)।

[2]

6. **सामाजिक आर्थिक विकास की कम संभावनाओं ने नौकरियों और शिक्षा के लिए पलायन को बढ़ावा दिया है, जिससे असम में उच्च-स्तरीय कौशल की कमी हो गई है। टीवीईटी और उच्च शिक्षा की आपूर्ति कम है, और मौजूदा प्रणालियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निम्न गुणवत्ता और उद्योग प्रासंगिकता शामिल है, जिसके कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और शैक्षणिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से स्नातकों की खराब रोजगार क्षमता है। आगे के अध्ययन या कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थानों और कार्यक्रमों के बीच प्रगति और गतिशीलता के रास्ते की कमी और आईटीआई और पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षकों और शिक्षकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण प्रणाली।**

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)। 2020 *असम: आसियान के लिए भारत का प्रवेश द्वार।* मनीला; ए 2020। "पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारा: लोगों और बाजारों को एक साथ लाना"। प्रस्तुतिकरण मनीला।

मानचित्र 1: असम कौशल विश्वविद्यालय का स्थान

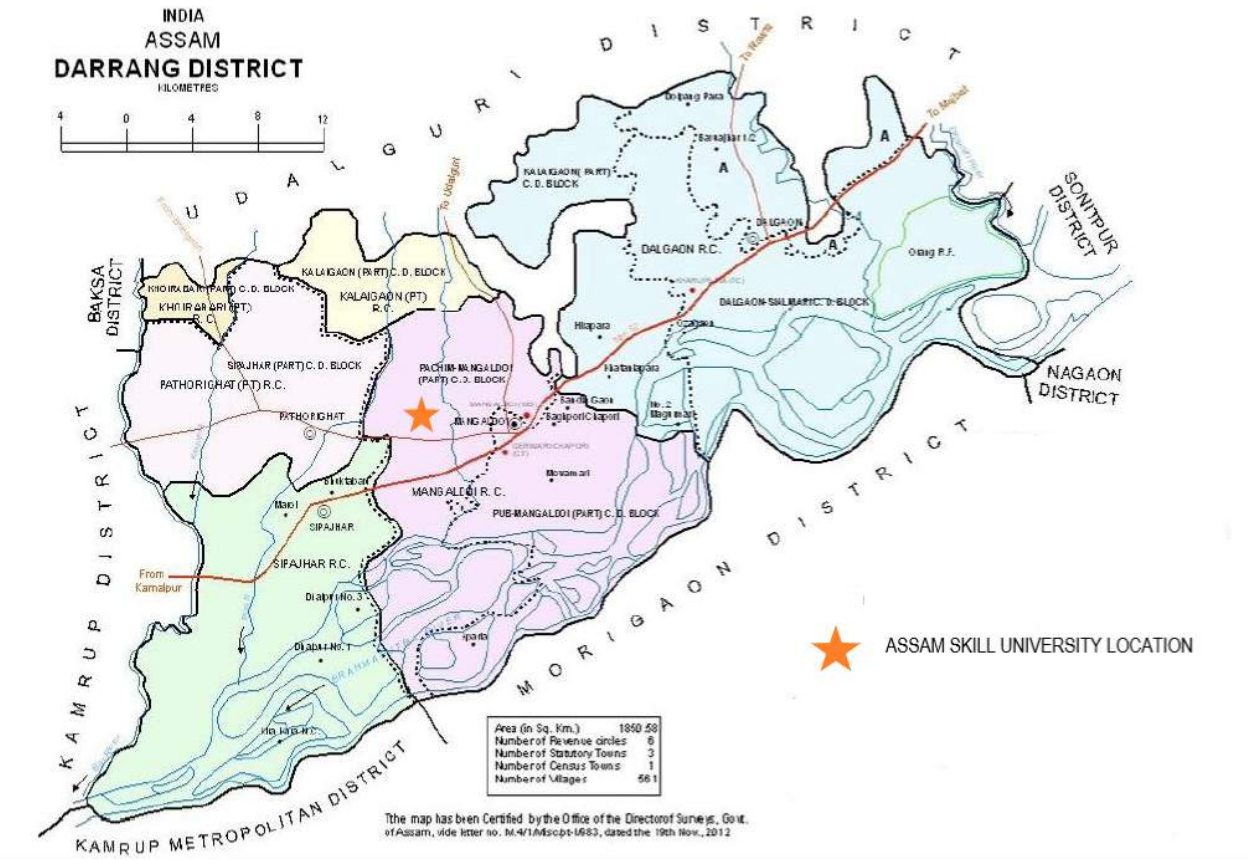

7. **सितंबर 2020 में, असम विधान सभा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुपालन में असम कौशल विश्वविद्यालय (एएसयू) की स्थापना के लिए असम कौशल विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया। असम सरकार ने एएसयू को अपने परिसर और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुविधाओं के साथ और उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत उच्च गुणवत्ता, उद्योग-संरेखित, और लचीली कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना; आचरण अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; उद्यमिता और व्यापार स्टार्टअप का समर्थन करना और असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कौशल स्तर बढ़ाने के लिए एक प्रीमियम संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित करने की परिकल्पना की है। सरकार को यह भी उम्मीद है कि एएसयू छात्रों, टीवीईटी और उच्च शिक्षा संस्थानों और पड़ोसी देशों के उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगा, जो कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण में समान चुनौतियों का सामना करते हैं, और जिनके साथ राज्य के लंबे समय से संबंध हैं। ASU गुवाहाटी से लगभग 74 किमी पूर्व में स्थित मंगलदोई में होगा, और गुवाहाटी को असम के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 27 (NH-27) के 25 किमी के भीतर होगा। NH-27 परिवहन के अन्य साधनों (यानी, वायुमार्ग, जलमार्ग और रेलवे) के साथ एकीकृत है और पड़ोसी राज्यों और देशों को महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करता है।**

परियोजना के लिए किया गया एक गहन कौशल अंतर विश्लेषण असम में निम्नलिखित उद्योगों में उच्च-स्तरीय कौशल की बढ़ती मांगों को दर्शाता है: कृषि और खाद्य उत्पादन; मोटर वाहन; निर्माण; रचनात्मक उद्योगों; इलेक्ट्रॉनिक्स; अक्षय और वैकल्पिक ऊर्जा सहित ऊर्जा; स्वास्थ्य सेवा; सूचान प्रौद्योगिकी; पर्यटन और कल्याण।[3] कौशल अंतर विश्लेषण के आधार पर, और असम में नियोजित और चल रही प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे, जलविद्युत, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क), साथ ही साथ एडीबी अध्ययन (फुटनोट 2),[4] और अखिल भारतीय, क्षेत्रीय और वैश्विक कौशल अध्ययन, नौ संकायों पर विचार करते हुए एएसयू का हिस्सा बनने के लिए पहचान की गई है: संकाय (i) कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी; (ii) प्रौद्योगिकी; (iii) डिजाइन और रचनात्मकता; (iv) विनिर्माण और निर्माण; (v) स्थिरता; (vi) गतिशीलता; (vii) प्रबंधन और वित्त; (viii) पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य; और (ix) स्वास्थ्य देखभाल। इसके अलावा, एएसयू उद्यमिता और नवाचार के संकायों में सभी उम्र के लिए उद्यमशीलता और अनुप्रस्थ कौशल के विकास का समर्थन करेगा; जीवन कौशल और भाषाएं; आजीवन सीखना; और पाठ्यक्रम और संकाय विकास (एएसयू संकाय, प्रशिक्षकों और आईटीआई और पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए)।

B. परियोजना विवरण

8. असम कौशल विश्वविद्यालय परियोजना असम में अपनी कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत करने में असम सरकार की सहायता करेगी। यह सभी के लिए अच्छा रोजगार सुनिश्चित करने और समावेशी और सतत बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार के लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान देगा।[5] परियोजना के पांच आउटपुट होंगे।

9. **आउटपुट 1: यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस मॉडल और फैकल्टी डेवलपमेंट और मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किए गए।** एएसयू के सतत संचालन के लिए, परियोजना एएसयू के विकास का समर्थन करेगी; (i) प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम (ii) नेतृत्व और प्रबंधन कौशल; (iii) छात्र सेवा प्रणाली और कार्यक्रम; (iv) कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों,

---

[3] केजी. 2020 *असम राज्य के लिए माइक्रो-लेवल स्किल गैप स्टडी।* इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार और हेल्थकेयर। केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

[4] अध्ययन असम में उच्च शिक्षा, चिकित्सा पर्यटन, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल, और कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विकास क्षमता की ओर इशारा करते हैं।

[5] परिवर्तन और विकास विभाग, असम सरकार। 2018 *असम एजेंडा 2030: सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ और कार्य।* गुवाहाटी।

अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास, और अन्य सेवाओं के लिए व्यवसाय और वित्त पोषण मॉडल; (v) संकाय भर्ती, व्यावसायिक विकास, प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन प्रणाली; और (vi) डिजिटल कैंपस प्लेटफॉर्म, जिसमें शिक्षण और सीखने के प्रबंधन के लिए सिस्टम शामिल हैं; भवन और सुविधा प्रबंधन; श्रम बाजार खुफिया; प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा (जैसे, अनुकरण, संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता); और ऑनलाइन शिक्षा। कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट और रास्ते का एक ढांचा विकसित किया जाएगा, जिसमें पूर्व शिक्षा की मान्यता भी शामिल है। एएसयू में महिलाओं और वंचित समूहों के हित और नामांकन को बढ़ावा देने की रणनीतियां भी विकसित की जाएंगी।

10. **आउटपुट 2: पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जलवायु लचीला विश्वविद्यालय परिसर और विकसित सुविधाएं।** यह परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल एएसयू परिसर के डिजाइन और निर्माण और अत्याधुनिक तकनीकों जैसे, (शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाएं, व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं, पुस्तकालय, छात्रावास, छात्र अवकाश सुविधाओं) से लैस सुविधाओं का समर्थन करेगी। एएसयू परिसर और सुविधाएं हरित भवन मानकों का पालन करेंगी, और ऊर्जा और जल बचत प्रणालियों, और जलवायु अनुकूलन उपायों को अपनाएंगी। उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए एक स्थायी परिसर और सुविधा प्रबंधन रणनीति विकसित की जाएगी। महिलाओं और वंचित समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं को एएसयू परिसर और सुविधाओं के डिजाइन में शामिल किया जाएगा।

11. **आउटपुट 3: उद्योग-संरेखित और लचीली कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन और वितरित किए गए।** यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संस्थानों और उद्योगों के सहयोग से, एनएसक्यूएफ स्तर 4 और उससे ऊपर (प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बी. वोक, पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा, एम. Voc., और Ph.D.), और अन्य उन्नत कौशल, करियर विकास, सॉफ्ट स्किल्स, और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ-साथ पेशेवरों के लिए एएसयू में भाषा कौशल कार्यक्रम और अन्य कामकाजी उम्र की आबादी के लिए है। ये कार्यक्रम (i) उद्योग के सहयोग से विभिन्न तौर-तरीकों (जैसे, ऑन-कैंपस, ऑफ-कैंपस, ऑनलाइन, "हब-एंड-स्पोक", संस्थान-उद्योग-संघ) में डिज़ाइन और वितरित किए जाएंगे; (ii) लचीला प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा (iii) ब्रिज कोर्स पूरा करने की संभावना के साथ, पूर्व सीखने की मान्यता की अनुमति देता है; (iv) उद्योग के सहयोग से कौशल के मूल्यांकन और प्रमाणन की आवश्यकता है; (v) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन एजेंसियों द्वारा प्रत्यायित होना; और (vi) पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन, और उद्यमिता पर मॉड्यूल को एकीकृत करना है। यह परियोजना (i) छात्रों के लिए कैरियर विकास कार्यक्रमों, सेवाओं और संसाधनों के विकास का भी समर्थन करेगी, जिसमें महिला छात्रों और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम और सेवाएं

शामिल हैं, ताकि उन्हें सफल होने में मदद मिल सके, खासकर गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में; (ii) संचार और सहयोग, और विदेशी भाषा कौशल जैसे सॉफ्ट कौशल विकसित करने के लिए कार्यक्रम; और (iii) सतत शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें सूक्ष्म और वैकल्पिक क्रेडेंशियल कार्यक्रम और उद्योग भागीदारों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम शामिल हैं।

12. **आउटपुट 4: उद्यमिता का प्रबंधन और समर्थन करने की क्षमता, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास, और विकसित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।** परियोजना उद्यमिता और नवाचार के स्कूल की स्थापना का समर्थन करेगी जो (i) उद्योग भागीदारों, पूर्व छात्रों, व्यावसायिक सहायता और वित्त पोषण संगठनों के नेटवर्क को उद्योग सगाई और वाणिज्यिक उद्यमों के कार्यालय के माध्यम से विकसित और प्रबंधित करेगी; (ii) अन्य स्कूलों को उद्यमिता शिक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करना; (iii) इनक्यूबेटर सुविधाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन; (iv) एएसयू और उद्योग भागीदारों के लिए संयुक्त और अनुबंध आर एंड डी, परामर्श, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रबंधन; और (v) अन्य स्कूलों को उद्योग और अन्य संस्थागत भागीदारों के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के विकास, प्रबंधन और संचालन के लिए सहायता प्रदान करना। उद्यमिता शिक्षा और समर्थन, अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। उद्योग और अन्य संस्थानों के सहयोग से उद्योग-विशिष्ट प्रौद्योगिकी सेवा, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, जो डिजिटल और हरित परिवर्तन को बढ़ावा देंगे, का भी समर्थन किया जाएगा।

13. **आउटपुट 5: असम, अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों में व्यावसायिक विकास और गुणवत्ता कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुंच में सुधार हुआ है।** एएसयू में विभिन्न स्कूलों में विकसित प्रणालियों, संसाधनों और नेटवर्क पर आधारित, परियोजना एएसयू को असम में आईटीआई और पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकन कर्ताओं के लिए व्यावसायिक विकास और गुणवत्ता कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करने में और अन्य राज्यों, और पड़ोसी देशों (जैसे, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल) में TVET और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी के लिए सहायता करेगी। परियोजना संकाय और पाठ्यक्रम विकास के स्कूल की स्थापना का समर्थन करेगी जो (i) निर्देश, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पर शोध करेगा; (ii) एएसयू के संकाय और स्टाफ सदस्यों के निरंतर व्यावसायिक विकास का समर्थन करना; (iii) असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आईटीआई और पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित और वितरित करना; और (iv) अत्याधुनिक पाठ्यक्रम, निर्देशात्मक और मूल्यांकन रणनीतियों और दृष्टिकोणों और प्रशिक्षण सामग्री का विकास और प्रसार करना। आईटीआई और पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के व्यावसायिक

विकास के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, यह परियोजना एएसयू को पड़ोसी देशों में टीवीईटी और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाने और विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों के केंद्र में अपने स्थानीय लाभ का लाभ उठाते हुए सामान्य रणनीतिक उद्योगों के लिए कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने में सहायता करेगी।

III. असम में स्वदेशी लोगों का अवलोकन

14. एडीबी के एसपीएस (2009) में "स्वदेशी लोगों" शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में एक विशिष्ट, कमजोर, सामाजिक और सांस्कृतिक समूह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें अलग-अलग डिग्री में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: (i) आत्म-पहचान एक विशिष्ट स्वदेशी सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के रूप में और दूसरों द्वारा इस पहचान की मान्यता; (ii) परियोजना क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से भिन्न आवासों या पैतृक क्षेत्रों और इन आवासों और क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के लिए सामूहिक लगाव; (iii) प्रथागत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, या राजनीतिक संस्थान जो प्रमुख समाज और संस्कृति से अलग हैं; और (iv) एक अलग भाषा, जो अक्सर देश या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा से भिन्न होती है। एडीबी का एसपीएस (2009) विभिन्न देशों में स्वदेशी लोगों की विविधता को मान्यता देता है और नोट करता है कि राष्ट्रीय कानून, प्रथागत कानून, और किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें देश एक पार्टी है, पर विचार किया जाना चाहिए।

15. भारत में, "अनुसूचित जनजातियाँ" भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्दिष्ट हैं और सामान्य रूप से उन समुदायों को संदर्भित करती हैं जिनकी विशेषता है: (i) आदिम लक्षण; (ii) विशिष्ट संस्कृति; (iii) भौगोलिक अलगाव; (iv) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच; और (v) पिछड़ापन। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को पहले संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेशों के माध्यम से नामित किया जाएगा और बाद में संसद के अधिनियमों के माध्यम से संशोधित किया जाएगा। मार्च 2021 तक, नौ आदेश और आठ अधिनियम हैं जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हैं।

16. असम में, 23 अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं जिन्हें मोटे तौर पर "सादे" और "पहाड़ी" जनजातियों में बांटा गया है।[6] प्रमुख अनुसूचित जनजाति समूहों में बोडो (35.1%), मिशिंग (17.5%), कार्बी (11.1%), राभा

[6] असम सरकार। 2014. *असम मानव विकास रिपोर्ट 2014*। गुवाहाटी।

(7.6%), सोनोवाल कचारी (6.5%), लालुंग (5.2%), गारो (4.2%), और दीमासा शामिल हैं। (3.2%) और राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का 90% है।

17. 2011 की जनगणना (तालिका 1) के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के लोगों के उच्च अनुपात वाले जिलों में दीमा-हसाओ (70.9%), कार्बी आंगलोंग (56.3%), धेमाजी (47.4%), चिरांग (37.1%), बक्सा (34.8%) शामिल हैं।), उदलगुरी (32.1%), और कोकराझार (31.4%)। अनुसूचित जनजाति की 94.4% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
18. अनुसूचित जनजाति की आबादी में लिंगानुपात 984 था, जो राज्य (903) से अधिक और राष्ट्रीय औसत (990) के करीब था।

तालिका 1: असम में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, जिलावार (2011) से

संख्या	जिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या				कुल जनसंख्या		
			कुल जनसंख्या का %	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
	असम	**12,4 1.957.005 1.927.366 31.205.576 15.939.443 14.402.855**						**3.884.371**
1	**कोकराझार**	31,4 139.579 139.086 887.142 452.905 434.237						278.665
2	**धुबरी**	6,332	0.3	3,198	3,134	1,949,258	997,848	951,410
3	**गोलपारा**	231,570	23.0	116,013	115,557	1,008,183	513,292	494,891
4	**बारपेटा**	27,344	1.6	13,530	13,814	1,693,622	867,004	826,618
5	**मोरीगांव**	136,777	14.3	68,382	68,395	957,423	486,651	470,772
6	**नगांव**	57.759 57.394 2.823.768 1.439.112 1.384.656	4,1					115.153
7	**सोनितपुर**	117.685 114.522 1.924.110 983.904 940.206	12,1					232.207
8	**लखीमपुर**	23,9 126.716 122.710 1.042.137 529.674					249.426	512,463
9	**धेमाजी**	47,4 165.449 160.111 686.133 351.249 334.884						325.560
10	**तिनसुकिया**	6,2 41.769 40.297 1.327.929 680.231 647.698						82.066
11	**डिब्रूगढ़**	7,8 51.835 51.036 1.326.335 676.434 649.901						102.871
12	**शिवसागर**	4,3 24.989 24.050 1.151.050 589.216 561.834						49.039

13	**जोरहाट**	70.795 69.176 1.092.256 556.805 535.451	12,8					139.971
14	**गोलाघाट**	111,765	10.5	55.345 1.066.888 543.161 523.727				56.420
15	**कार्बी आंगलोंग**	56,3 272.460 266.278 956.313 490.167 466.146						538.738
16	**दीमा-हसाओ**	70,9 76.520 75.323 214.102 110.802 103.300						**151.843**
17	**कछार**	8.736 8.833 1.736.617 886.284	1,0				17.569	850,333
18	**करीमगंज**	0,11.228.686 625.864 602.822		994	946			1.940
19	**हैलाकांडी**	0,1659.296 337.890 321.406		354	337			691
20	**बोंगईगांव**	9.377 9.458 738.804 375.818 362.986	2,5					18.835
21	**चिरांग**	37,1 89.273 89.415 482.162 244.860					178.688	237,302
22	**कामरूप**	182,038	12.0	92,094	89,944	1,517,542	778,461	739,081
23	**कामरूप (एम)**	75,121	6.0	37,902	37,219	1,253,938	647,585	606,353
24	**नलबाड़ी**	11.692 11.672 771.639 396.006 375.633	3,0					23.364
25	**बक्सा**	34,8 165.634 165.373 950.075 481.330 468.745						331.007
26	**दरांग**	0,9 4.300 4.119 928.500 475.273					8.419	453,227
27	**उदलगुरी**	267,372	32.1	133,550	133,822	831,668	421,617	410,051

नोट: 15 अगस्त 2015 को, उपरोक्त 27 जिलों के अलावा पांच नए जिले (बिस्वनाथ, चराईदेव, होजई, दक्षिण सलमारा-मनकाचर, पश्चिम कार्बी आंगलोंग) का गठन किया गया था। 27 जून 2016 को माजुली को भी जिला घोषित किया गया था। मार्च 2021 तक, राज्य को 33 जिलों में विभाजित किया गया है।

स्रोत: गृह मंत्रालय। 2014. *भारत की जनगणना, 2011*। नई दिल्ली।

19. **2011 की जनगणना ने संकेत दिया कि अनुसूचित जनजाति की आबादी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हो सकती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत राज्य के औसत (31.9%; ग्रामीण क्षेत्रों में 33.9%; शहरी क्षेत्रों में 20.5%) की तुलना में अनुसूचित जनजाति की आबादी (40.5%) में अधिक था। अनुसूचित जनजाति के 18.6% परिवारों ने बताया कि उनके पास टिकाऊ घरेलू संपत्ति की कमी है और उनके पास बैंकिंग सेवाओं और ग्रिड बिजली तक सीमित पहुंच है। अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच साक्षरता दर राज्य में समग्र औसत (72.2%) से थोड़ी कम (72.1%) थी, इसके साथ ही महिलाओं के लिए काफी पिछड़ी हुई (65.0%; असम में 66.3%)। इसी तरह, अनुसूचित जनजाति की आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के बीच शैक्षिक प्राप्ति का स्तर कम था, 55% के पास केवल**

प्राथमिक शिक्षा थी या बिल्कुल भी शिक्षा नहीं थी (असम में 49%), 25% ग्रेड 8 (23% असम में) पूरा कर रहे थे। और 2012 में 20% ग्रेड 10 और उससे अधिक (असम में 27%) प्राप्त कर रहे हैं।

20. अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ शिक्षा में छात्रों का नामांकन सामान्य रूप से राज्य और राष्ट्रीय औसत से अधिक है (तालिका 2)। उदाहरण के लिए, असम में अनुसूचित जनजाति के युवाओं में माध्यमिक शिक्षा (ग्रेड IX-X) में सकल नामांकन अनुपात (GER) वित्तीय वर्ष (FY) 2016 में 99.9% था, जो राज्य में समग्र औसत (77.6%) से अधिक था और राष्ट्रीय स्तर पर (80.0%) । वित्त वर्ष 2016 में समग्र राज्य (38.8%) और राष्ट्रीय (56.2%) औसत और उच्च शिक्षा में जीईआर की तुलना में अनुसूचित जनजाति के युवाओं में 50.6 फीसदी पर वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा (ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षा) में जीईआर के मामले में भी यही स्थिति थी। 2018-2019 में राज्य (18.7%) और राष्ट्रीय (26.3%) औसत के विपरीत अनुसूचित जनजाति के युवाओं में 24.3%। वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च शिक्षा में, अनुसूचित जनजाति समूहों की लड़कियों की पहुंच असम में अनुसूचित जनजाति समूहों के लड़कों की तुलना में थोड़ी कम है।

तालिका 2: असम और भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात

मद	असम			अखिल भारतीय		
	लड़कियों	लड़कों	कुल	लड़कियों	लड़कों	कुल
प्रारंभिक शिक्षा में GER	104.56	98.82	101.62	99.59	94.53	96.91
अनुसूचित जनजाति के लिए GER	119.56	115.57	117.52	103.09	103.41	119,56
माध्यमिक शिक्षा में GER	83.04	72.48	77.59	80.97	79.16	80.01
अनुसूचित जनजाति के लिए GER	101.51	98.28	99.88	75.38	73.74	101,51
सीनियर सेकेंडरी शिक्षा के क्षेत्र में GER	39.47	38.22	38.81	56.41	55.95	56.16
अनुसूचित जनजाति के लिए GER	49.16	52.03	50.63	42.44	43.76	43.12
उच्च शिक्षा में GER	18.3	19.1	18.7	26.4	26.3	26.3
अनुसूचित जनजाति के लिए GER	23.1	25.6	24.3	16.5	17.9	17.2

जीईआर = सकल नामांकन अनुपात, एसटी = अनुसूचित जनजाति।

* प्रारंभिक शिक्षा में ग्रेड I-VIII, माध्यमिक शिक्षा में ग्रेड IX-X और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा में ग्रेड XI-XII शामिल हैं। आंकड़े 2015-2016 के हैं।

** डेटा 2018-2019 के लिए हैं।

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2018 *शैक्षिक सांख्यिकी एक नजर में* नई दिल्ली; मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2019 *उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-2019*। नई दिल्ली।

21. हालांकि, अनुसूचित जनजाति के युवाओं में सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन (हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन इन असम), में पास होने का दर पिछड़ा हुआ नजर आता है। 2017 में, जबकि राज्य में कुल पास होने की दर 54.2% थी, जबकि अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए यह 36.4% थी। अनुसूचित जनजाति के युवाओं में, मैदानी जनजाति समूहों के लड़कियों और युवाओं ने पहाड़ी जनजाति समूहों (लड़कियों के लिए 30.0 प्रतिशत, लड़कों के लिए 34.2 प्रतिशत, 32.1%) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया (लड़कियों के लिए 39.2%, लड़कों के लिए 42.0%, दोनों के लिए 40.6%) दोनों के लिए)।

22. TVET के संबंध में, अनुसूचित जनजाति समूहों के छात्रों का अनुपात अधिक है, यह देखते हुए कि अनुसूचित जनजाति की आबादी असम में कुल जनसंख्या का 12.4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है। FY2019 और FY 2020 में, राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुसूचित जनजाति समूहों के छात्रों का प्रतिशत 13.3% था और राज्य सरकार के पॉलिटेक्निक में 16.3% था। कम महिला छात्र इंजीनियरिंग कॉलेजों (25.0%) और पॉलिटेक्निक (19.4%) में दाखिला लेती हैं। राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में नामांकित छात्राओं में अनुसूचित जनजाति समूह की छात्राओं की संख्या 15.7% थी।[7]

23. हालांकि आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, आईटीआई में छात्रों के नामांकन से एक समान तस्वीर उभरती है। अनुमानों के आधार पर, वित्त वर्ष 2020 में आईटीआई में अनुसूचित जनजाति समूहों के छात्रों का अनुपात 17.8% (महिला छात्रों के लिए 20.0%, पुरुष छात्रों के लिए 17.0%) था।[8]

IV. सामाजिक प्रभाव आकलन

24. यह देखते हुए कि एएसयू में भावी छात्र ड्रॉपआउट और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों, और विश्वविद्यालयों के साथ-साथ पेशेवरों और अन्य कामकाजी उम्र की आबादी से स्नातक होंगे, इस परियोजना के अनुसूचित पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। असम में जनजाति आबादी को उद्योग-संरेखित कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण तक बेहतर पहुंच के साथ, जो उच्च-भुगतान, अच्छी नौकरी पाने की उनकी संभावना को बढ़ाएगा। परियोजना के परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति की आबादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

[7] असम सरकार। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय। 2020 *सांख्यिकी हैंडबुक असम-2019*। गुवाहाटी।

[8] असम कौशल विकास मिशन (एएसडीएम) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर अनुमानित।

25. इसके अलावा, इस परियोजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी को भी लाभ होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 200 अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में अनुसूचित जनजाति की आबादी 80% से अधिक है। एएसयू न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों सहित पूरे भारत के छात्रों को प्रवेश देगा, बल्कि क्षेत्र में आईटीआई और पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षकों और शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास और गुणवत्ता कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुंच में सुधार करेगा।

26. अनुसूचित जनजाति आबादी पर परियोजना के संभावित सकारात्मक प्रभावों को तालिका 3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3: आउटपुट द्वारा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पर सकारात्मक प्रभाव

आउटपुट	संभावित सकारात्मक प्रभाव
आउटपुट 1: विश्वविद्यालय प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम, व्यवसाय मॉडल, और संकाय विकास और प्रबंधन प्रणाली का विकास	अनुसूचित जनजाति समुदायों और उनके परिवारों के भावी छात्रों को एएसयू में उनके नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। एएसयू में अनुसूचित जनजाति समूहों के छात्रों को छात्र सेवाएं प्राप्त होंगी। अनुसूचित जनजाति समूहों सहित महिलाओं और वंचित समूहों की रुचि, और नामांकन और रोजगार को एएसयू में रणनीतियों की तैयारी और कार्यान्वयन के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
आउटपुट 2: पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जलवायु लचीला विश्वविद्यालय परिसर और विकसित सुविधाएं	अनुसूचित जनजाति समूहों के छात्रों को एएसयू परिसर और शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं, व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं सहित अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुविधाओं तक पहुंच होगी। पुस्तकालय, छात्र और कर्मचारी आवासीय सुविधाएं।
आउटपुट 3: उद्योग से जुड़े और लचीले कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए और वितरित किए गए	वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के स्नातकों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति समूहों के पेशेवरों और अन्य कामकाजी उम्र की आबादी तक पहुंच होगी। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क स्तर 4 और उससे ऊपर के कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एएसयू में अन्य उन्नत कौशल, करियर विकास, सॉफ्ट कौशल और भाषा कौशल कार्यक्रमों के लिए। महिला छात्रों और अनुसूचित जनजाति समूहों सहित वंचित समूहों के लोगों को विशेष कैरियर विकास कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

आउटपुट 4: उद्यमिता का प्रबंधन और समर्थन करने की क्षमता, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विकास	अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं और वयस्कों को एएसयू में पेश की जाने वाली इनक्यूबेटर सुविधाओं और कार्यक्रमों से लाभ होगा। अनुसूचित जनजाति समूहों के संकाय सदस्यों और छात्रों को अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दिशानिर्देश, आचार संहिता और नैतिकता, प्रोत्साहन और समर्थन तंत्र पर भी प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
आउटपुट 5: असम, अन्य राज्यों और पड़ोसी देशों में व्यावसायिक विकास और गुणवत्ता कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुंच में सुधार हुआ	एएसयू संकाय और कर्मचारी, आईटीआई के प्रशिक्षकों और संकाय और अनुसूचित जनजाति समूहों के पॉलिटेक्निक के पास एएसयू द्वारा पेश किए गए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों तक पहुंच होगी। .

एडीबी = एशियाई विकास बैंक, एएसयू = असम कौशल विश्वविद्यालय, आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आर & डी = अनुसंधान और विकास।

स्रोत: एडीबी।

27. **स्वदेशी लोगों के लिए लागू कानूनी और संस्थागत ढांचा।** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और असम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण), संशोधन सहित विधायिका के अधिनियमों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की आबादी के अधिकारों की रक्षा की जाती है, अधिनियम, 2012 । असम सरकार की, सादा जनजातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है, और अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए योजनाएं और योजनाएं तैयार करता है और लागू करता है, जिसमें छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता शामिल है। अनुसूचित जनजाति समूहों के छात्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्र विभाग असम स्वायत्त जिलों (जिला परिषदों का संविधान) नियम, 1951 (1987 में संशोधित) के तहत गठित दो स्वायत्त परिषदों (कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और उत्तरी कछार हिल स्वायत्त परिषद) का प्रशासनिक विभाग है। विभाग दो पहाड़ी जिलों (कार्बी आंगलोंग और दीमा-हसाओ) के लिए जिम्मेदार है, और स्वायत्त परिषदों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के आधार पर योजनाओं के लिए धन तैयार करता है, समन्वय करता है, निगरानी करता है, मूल्यांकन करता है और आवंटित करता है।

28. **स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के नीतिगत सिद्धांत।** अनुसूचित जनजाति की आबादी पर परियोजना के संभावित सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने के लिए, एडीबी के एसपीएस (2009) में निर्धारित स्वदेशी लोगों के सुरक्षा उपायों के निम्नलिखित नीति सिद्धांत परियोजना पर लागू होते हैं:

(i) स्क्रीन जल्दी निर्धारित करने के लिए (ए) क्या स्वदेशी लोग मौजूद हैं , या परियोजना क्षेत्र से सामूहिक लगाव है; और (ख) क्या स्वदेशी लोगों पर परियोजना के प्रभाव की संभावना है।

(ii) एक सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और लिंग-संवेदनशील सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना या स्वदेशी लोगों पर सकारात्मक और प्रतिकूल दोनों संभावित परियोजना प्रभावों का आकलन करने के लिए समान तरीकों का उपयोग करना। परियोजना लाभ के प्रावधान और शमन उपायों

के डिजाइन के संबंध में प्रभावित स्वदेशी लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले विकल्पों पर पूरा विचार करना। प्रभावित स्वदेशी लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक लाभों की पहचान करना जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और लिंग और अंतर-पीढ़ी में समावेशी हैं और स्वदेशी लोगों पर प्रतिकूल प्रभावों से बचने, कम करने और / या कम करने के उपाय विकसित करते हैं।

(iii) प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों और संबंधित स्वदेशी लोगों के संगठनों के साथ सार्थक परामर्श करना ताकि उनकी भागीदारी (ए) प्रतिकूल प्रभावों से बचने के उपायों को डिजाइन करने, लागू करने और निगरानी करने में या, जब टालना संभव न हो, ऐसे प्रभावों को कम करने, कम करने या क्षतिपूर्ति करने के लिए ; और (बी) प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से परियोजना लाभों को तैयार करने में। स्वदेशी लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रभावित करने वाली परियोजनाएं सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और लिंग समावेशी क्षमता विकास प्रदान करेंगी। स्वदेशी लोगों की चिंताओं को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और लैंगिक समावेशी शिकायत तंत्र स्थापित करना।

(iv) एक आईपीपी तैयार करना, जो योग्य और अनुभवी विशेषज्ञों की सहायता से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर आधारित हो और जो प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों द्वारा स्वदेशी ज्ञान और भागीदारी पर आधारित हो। आईपीपी में परियोजना कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों के साथ निरंतर परामर्श के लिए एक ढांचा शामिल है; यह सुनिश्चित करने के उपायों को निर्दिष्ट करता है कि स्वदेशी लोगों को सांस्कृतिक रूप से उचित लाभ मिले; किसी भी प्रतिकूल परियोजना प्रभाव से बचने, कम करने, कम करने या क्षतिपूर्ति करने के उपायों की पहचान करता है; और इसमें सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त शिकायत प्रक्रिया, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था, और नियोजित उपायों को लागू करने के लिए एक बजट और समयबद्ध कार्रवाई शामिल है।

(v) परियोजना मूल्यांकन से पहले, समयबद्ध तरीके से परामर्श प्रक्रिया के दस्तावेज़ीकरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के परिणामों सहित, एक सुलभ स्थान पर और प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों और अन्य हितधारकों के लिए समझने योग्य रूप में और भाषा (एस) में एक मसौदा आईपीपी का खुलासा करें। . अंतिम आईपीपी और इसके अद्यतनों का भी प्रभावित स्वदेशी लोगों के समुदायों और अन्य हितधारकों के सामने खुलासा किया जाएगा।

(vi) योग्य और अनुभवी विशेषज्ञों का उपयोग करके आईपीपी के कार्यान्वयन की निगरानी करना; जहां भी संभव हो, भागीदारी निगरानी दृष्टिकोण अपनाएं; और आधारभूत स्थितियों और आईपीपी निगरानी के परिणामों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करें कि क्या आईपीपी के उद्देश्य और वांछित परिणाम प्राप्त किए गए हैं। निगरानी रिपोर्ट का खुलासा करें।

V. सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और भागीदारी

29. स्वदेशी लोगों के मूल्यांकन सहित एक गरीबी, सामाजिक और लिंग मूल्यांकन प्रासंगिक राष्ट्रीय और राज्य कानूनों, नीतियों, डेटा और अध्ययनों की व्यापक दस्तावेज़ समीक्षाओं और राष्ट्रीय सामाजिक विकास द्वारा प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से किया गया था। और लिंग विशेषज्ञ (परामर्शदाता) नवंबर २०२०-फरवरी २०२१ में परियोजना की तैयारी और उचित परिश्रम के लिए लगे हुए हैं। जिन लोगों से परामर्श किया गया उनमें एएसयू परिसर स्थल के आसपास के स्थानीय समुदाय, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन के कर्मचारी, और महिला और पुरुष छात्र, प्रशिक्षक और प्लेसमेंट अधिकारी शामिल थे। तीन टीवीईटी संस्थान, साथ ही राज्य सरकार के अधिकारी और उद्योग संघ हैं। टीवीईटी संस्थानों में महिला और पुरुष छात्रों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन भी आयोजित किया गया। परामर्श के दौरान ली गई तस्वीरें और आयोजित परामर्शों का विवरण परिशिष्ट 1 और 2 में दिया गया है।

30. मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य थे (i) समग्र सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना जिसमें एएसयू संचालित होगा; (ii) अच्छे रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं की पहचान करना और कारकों को सुविधाजनक बनाना; (iii) एएसयू परिसर स्थल के आसपास स्थानीय समुदायों की चिंताओं और अपेक्षाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना; (iv) परियोजना कार्यान्वयन चरण के दौरान प्रमुख हितधारकों का नक्शा तैयार करना; और (v) कौशल, करियर और आजीविका विकास के लिए महिला और पुरुष युवाओं और वयस्कों की आकांक्षा को समझना।

31. परामर्श से पता चला कि सभी प्रमुख हितधारकों ने अनुसूचित जनजाति समुदायों सहित परियोजना पर सकारात्मक प्रभाव डाला और राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र और भारत के समग्र विकास में योगदान दिया। हितधारकों ने यह भी स्वीकार किया कि इस परियोजना से सभी उम्र की महिलाओं और पुरुषों के बीच रोजगार और उद्यमिता के अवसरों में वृद्धि होगी। किसी भी हितधारक द्वारा किसी भी तरह से परियोजना का विरोध करने का कोई उदाहरण नहीं देखा गया था। हितधारकों के परामर्श से प्राप्त निष्कर्षों को तालिका 4 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4: हितधारक परामर्श के सारांश

क्षेत्र	धारणाएं / विचार
अनुसूचित जनजाति समुदाय	• अनुसूचित जनजाति समुदाय की संस्कृतियों को अक्सर कुछ मुख्यधारा की संस्कृति के साथ मिश्रित किया गया है और यह राज्य के प्रभुत्व में परिलक्षित होता है। • असम में कुछ अनुसूचित जनजाति समुदाय सुदूर ग्रामीण और वन क्षेत्रों में हैं और उच्च और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं तक उनकी सीमित पहुंच है

	• अनुसूचित जनजाति समुदायों का साक्षरता स्तर असम में समग्र जनसंख्या के बराबर है। हालांकि महिलाओं के लिए साक्षरता दर कम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। • अधिकांश अनुसूचित जनजाति आबादी कपड़ा, हथकरघा, और कला और शिल्प की एक श्रृंखला जैसे पारंपरिक व्यापार में संलग्न है, और एएसयू इनके कौशल को बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा। • पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदाय, एएसयू का लाभ प्राप्त कर सकता है। छात्रों के आउटरीच गतिविधियों के लिए COMP असम से परे वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा आयोजित की जानी चाहिए,
एएसयू में भावी छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि	• शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अधिकांश बच्चे असम में स्कूल जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियों के जल्दी विवाह के कारण कक्षा VII या VIII के बाद स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं और कम आय वाले परिवारों के लड़के घर या बाहर काम करते हैं। • बहुत कम छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए समय ले पाते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। • माता पिता अक्सर अपने बच्चों को, विशेष रूप से लड़कियों को, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा को लेने के लिए प्रेरित नहीं करते है।
युवाओं द्वारा कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण की मांग	वहाँ ग्रामीण जिलों में छात्रों के बीच कौशल और तकनीकी शिक्षा के अवसरों के बारे में बहुत कम जागरूकता है और छात्र अक्सर अर्ध या अकुशल नौकरी करने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं। • यदि छात्र खर्च कर सकते हैं, तो वे राज्य के बाहर पश्चिमी, पूर्वी या दक्षिणी भारतीय शहरों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना पसंद करते हैं। • यदि छात्रों को असम में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, तो भी उन्हें नौकरी के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है, चूंकि राज्य में बहुत कम विकास हुआ है। • अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं के पास पहले से ही वानिकी, पशुपालन, बागवानी, बुनाई (विशेषकर महिलाएं) और अन्य हस्तशिल्प में स्थानीय रूप से विकसित कौशल है। • छात्रों को देश भर में और यहां तक कि विदेश में रोजगार पाने योग्य होने के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता है। • पाठ्यक्रम का चयन अक्सर परिवार के द्वारा या लिंग भूमिका द्वारा परिभाषित किया गया है, और महिला छात्रों को शायद ही कभी विज्ञान या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रोत्साहित किया जाता है • छात्रों ने सुझाव दिया है कि स्कूल प्रणाली, राज्य में कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में शामिल होना चाहिए। • यह छात्रों को उनके माता-पिता की भागीदारी के साथ उपलब्ध विकल्पों के बारे में सलाह और मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। • कुछ निजी टीवीईटी संस्थानों ने औपचारिक या अनौपचारिक रूप से छात्रों को उनकी पसंद के साथ मदद करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, विशेष रूप से नौकरी की खोज के दौरान, कैरियर परामर्श एकीकृत किया है। • एएसयू के लिए जबरदस्त क्षमता है, जैसा कि टीवीईटी संस्थानों में छात्रों द्वारा विभिन्न स्तरों पर, व्यक्त किया गया है क्योंकि यह उन्हें उच्च स्तर का विकास और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर नौकरी या उद्यमिता के अवसर प्राप्त करने की अनुमति देगा • बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में शिक्षा या नौकरियों में लगे युवाओं ने नोवेल-कोरोनावायरस महामारी के दौरान असम लौटना शुरू कर दिया है और राज्य में व्यवसाय शुरू करने में अपनी रुचि व्यक्त की है
चुनौतियां	• एएसयू के लिए चुनौतियों को लागू करने के लिए छात्रों की पहचान करना और उन्हें प्रेरित करना

	• प्रचार गतिविधियों और तकनीकी शिक्षा और कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच, छात्रों और अभिभावकों के बीच सीमित है जो ज्यादातर कौशल विकास के अवसरों और करियर विकल्पों से अनजान हैं। • राज्य में कई स्थान हैं, खासकर ग्रामीण अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति खण्ड, जहां युवाओं की तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक पहुंच नहीं है • राज्य में उद्योगों की सीमित संख्या और बुनियादी ढांचे के विकास में धीमी प्रगति है, राज्य में कुशल कार्यबल को अवशोषित करने की क्षमता को सीमित करते हुए।
एएसयू के सुझाव	• स्थानीय समुदाय जो परंपरागत रूप से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, हैं जैसे कपड़ा और बुनाई, उनके मौजूदा कौशल को पहचानना आवश्यक है। • छात्रों को पर्यटन, स्वास्थ्य और कल्याण, जैविक खेती और मत्स्य पालन जैसे राज्य की रोजगार क्षमता से जुड़े कौशल के साथ प्रोत्साहित करना और लैस करना महत्वपूर्ण है। • संभावित पाठ्यक्रमों के बारे में जो अनुसूचित जनजाति समुदायों से अधिक छात्रों को आकर्षित करें उनके बारे में सोचना महत्वपूर्ण है।

एएसयू = असम कौशल विश्वविद्यालय, टीवीईटी = तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण।
स्रोत: एशियाई विकास बैंक और असम सरकार।

32. कार्यान्वयन के दौरान सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और भागीदारी। परियोजना में हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन के दौरान समय-समय पर परामर्श और फोकस समूह चर्चा आयोजित की जाएगी। अनुसूचित जनजाति समूहों की महिलाओं सहित परामर्श और चर्चा के दौरान व्यक्त किए गए सभी विचारों पर विचार किया जाएगा और यदि उपयुक्त हो, तो परियोजना गतिविधियों की योजना और निगरानी की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस आईपीपी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को असम कौशल विकास मिशन (एएसडीएम) और एडीबी की वेबसाइटों पर पोस्ट किया गया है। अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आईपीपी को स्थानीय भाषाओं में भी प्रकट किया गया है। ASDM द्वारा स्थापित परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) ASDM वेबसाइट पर नियमित रूप से परियोजना की जानकारी पोस्ट और अपडेट करेगी। इसके अलावा, संभावित छात्रों और उनके माता-पिता, विशेष रूप से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी और अन्य वंचित समूहों के बीच परियोजना पर जानकारी को सक्रिय रूप से प्रसारित करने के लिए प्रचार और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अर्धवार्षिक सामाजिक सुरक्षा उपायों की निगरानी रिपोर्ट का खुलासा एडीबी की वेबसाइट पर किया जाएगा।

VI. स्वदेशी लोगों के लिए कार्य योजना

33. मूल्यांकन और परामर्श के निष्कर्षों के आधार पर, अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण, कैरियर विकास, उद्यमिता कार्यक्रमों और सेवाओं एएसयू तक पहुंच में सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों को आवश्यक माना जाता है।

34. रणनीतियाँ। एएसयू, एएसयू प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम विकास के लिए परामर्श फर्म के समर्थन से एएसयू में अनुसूचित जनजाति आबादी सहित महिलाओं और वंचित समूहों के हित को बढ़ावा देने और नामांकन करने के लिए रणनीति तैयार करेगा और अपनाएगा।

35. आउटरीच। हितधारक परामर्श ने संभावित छात्रों और उनके परिवारों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने और उन तक पहुंचने की आवश्यकता का संकेत दिया, ताकि कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण, और उद्यमिता शिक्षा में उनकी भागीदारी में सुधार किया जा सके, समर्थन कार्यक्रम। पीएमयू, परियोजना प्रबंधन समर्थन और आउटरीच समर्थन के लिए परामर्श फर्मों के समर्थन के साथ, प्रचार और आउटरीच गतिविधियों के लिए एक योजना तैयार करेगा। जो संभावित छात्रों और उद्यमियों के बीच लक्षित समूहों विशेष रूप से सात जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च अनुपात के साथ, अनुसूचित जनजाति आबादी (पैरा 14 और 22), लक्षित समूहों तक पहुंचने, जागरूकता को बढ़ावा देने और सूचना का प्रसार करने के लिए मीडिया, और राज्य और जिला स्तर पर सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी और समुदाय-आधारित संगठनों में सहयोग करने के लिए प्रचार और आउटरीच गतिविधियों की पहचान करेगा।

36. छात्रों के लिए वजीफा, छात्रवृत्ति, और अन्य वित्तीय सहायता। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समर्थित अनुसूचित जनजाति समूहों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों को एएसयू में छात्रों पर लागू किया जाएगा। एएसयू संभावित छात्रों और उनके परिवारों को योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराएगा और अपनी छात्र सेवाओं के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाएगा।

37. छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं। एएसयू परिसर और सुविधाओं को महिला छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए सुविधाओं, सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के साथ बाधा मुक्त और सार्वभौमिक रूप से सुलभ तरीके से डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एएसयू की आवासीय सुविधाओं की जानकारी सभी संभावित छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जनजाति समूहों सहित वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को तरजीह दी जाएगी।

38. कैरियर विकास कार्यक्रम और सेवाएं, सॉफ्ट और भाषा कौशल विकास कार्यक्रम। एएसयू अपने कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रत्येक छात्र की प्रगति को ट्रैक करेगा और कैरियर विकास कार्यक्रमों और सेवाओं, और सॉफ्ट और भाषा कौशल विकास कार्यक्रमों को विकसित और वितरित करेगा, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समूहों सहित वंचित पृष्ठभूमि से महिला छात्रों और

छात्रों के लिए, उनकी मदद करने के लिए कौशल विकास, आगे के अध्ययन, उद्यमिता, नौकरी की खोज और करियर विकास में सफल होंगे।

39. उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम। साझेदारी समझौतों के तहत, एएसयू (i) कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी के स्कूलों में स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करेगा; (ii) प्रौद्योगिकी; (iii) डिजाइन और रचनात्मकता; (iv) विनिर्माण और निर्माण; (v) स्थिरता; (vi) गतिशीलता; (vii) प्रबंधन और वित्त; (viii) पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य; और (ix) स्वास्थ्य देखभाल। जहां उपयुक्त हो, पारंपरिक व्यवसायों में अनुसूचित जनजाति समुदायों सहित स्थानीय समुदायों के बीच मौजूदा कौशल के निर्माण के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

VII. शिकायत निवारण तंत्र एएसडीएम

40. पीएमयू, परियोजना के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) स्थापित करेंगे और निम्नलिखित माध्यमों से शिकायत दर्ज की जा सकती है:

(i) वेब आधारित: एएसडीएम और एएसयू की वेबसाइटों पर एक अलग कोना विकसित किया जाएगा ताकि जनता और प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायतों को ऑनलाइन कॉलम में दर्ज कर सकें।

(ii) टेलीफोन और ईमेल-आधारित: शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी का संपर्क विवरण (नाम, फोन नंबर और ईमेल पता) एएसडीएम और एएसयू की वेबसाइटों और परियोजना सूचना बोर्ड पर एएसयू परिसर साइट पर उपलब्ध होगा ताकि आम जनता और प्रभावित व्यक्ति कर सकें फोन कॉल और ईमेल द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज करें।

(iii) ASDM की लोक शिकायत निवारण प्रणाली: ASDM का मोबाइल एप्लिकेशन सिस्टम DAKSHA (डिजिटल एक्सेस टू नॉलेज एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ असम) एक बहुआयामी ऐप है। जो सभी हितधारकों को शिकायतों को दर्ज करने, मॉनिटर करने, ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए एक ही मंच पर लाएगा।

41. प्रभावित व्यक्ति/पीड़ित पक्ष अपनी शिकायत मौखिक रूप से या लिखित रूप में मंगलदोई में एएसयू साइट कार्यालय को दे सकते हैं, जिसे पूर्व-निर्माण और निर्माण चरणों के दौरान और एएसयू प्रशासन द्वारा स्थापित किया जाएगा, संचालन चरण। प्रभावित व्यक्तियों की शिकायत को पहले एएसडीएम (एएसडीएम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक) में साइट के प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा जो एएसयू परिसर स्थल पर इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। यदि एएसडीएम में साइट के प्रभारी अधिकारी

द्वारा 7 दिनों के भीतर मामले का समाधान नहीं किया जाता है, तो इसे एएसयू परिसर स्थल पर उस उद्देश्य के लिए गठित शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाएगा।

42. विश्वविद्यालय परिसर स्थल पर शिकायत निवारण समिति। जीआरसी अपनी मासिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और शिकायत मिलने के एक महीने के भीतर मुद्दों का समाधान करेगी। बैठक का एजेंडा बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले सभी सदस्यों और प्रभावित व्यक्तियों/पीड़ित पक्ष को स्थान, तिथि और समय के साथ परिचालित किया जाएगा। एएसयू परिसर स्थल पर जीआरसी का नेतृत्व एएसडीएम (एएसडीएम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक) में साइट के प्रभारी अधिकारी करेंगे और इसमें पीएमयू सिविल इंजीनियर, पीएमयू पर्यावरण विशेषज्ञ, पीएमयू लिंग और स्वदेशी लोग विशेषज्ञ और स्थानीय से एक निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। निर्माण पूर्व और निर्माण चरणों के दौरान पंचायत। यदि एक महीने के भीतर एएसयू परिसर स्थल पर जीआरसी द्वारा मामले का समाधान नहीं किया जाता है, तो एएसडीएम में साइट के प्रभारी अधिकारी इसे पीएमयू में जीआरसी के पास भेज देंगे। 2024 में चालू होने के बाद, एएसयू अनुसूचित जनजाति समूहों सहित छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सदस्यों और स्थानीय समुदायों की शिकायतों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एक जीआरसी स्थापित करेगा।

43. परियोजना प्रबंधन कार्यालय में शिकायत निवारण समिति। पीएमयू में जीआरसी उस शिकायत को देखेगा जिसका समाधान एएसयू परिसर स्थल पर जीआरसी द्वारा नहीं किया जाता है। पीएमयू में जीआरसी का नेतृत्व एएसडीएम मिशन निदेशक करेंगे और इसमें पीएमयू पर्यावरण विशेषज्ञ और लिंग और स्वदेशी लोग विशेषज्ञ, और पीएमयू / एएसडीएम वित्त प्रबंधक / अधिकारी शामिल होंगे। यदि एक महीने के भीतर पीएमयू में जीआरसी द्वारा मामले का समाधान नहीं किया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति या पार्टी मामले को परियोजना संचालन समिति (पीएससी) में ला सकती है। पीएमयू में जीआरसी भी पीएससी को शिकायत का उल्लेख कर सकता है।

44. पीड़ित व्यक्ति/पार्टी किसी भी समय मामले को न्यायालय में ला सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति एडीबी मुख्यालय या एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन (आईएनआरएम) में शिकायत प्राप्त करने वाले अधिकारी से सीधे (लिखित रूप में) संपर्क करके एडीबी जवाबदेही तंत्र का उपयोग कर सकता है। जवाबदेही तंत्र में शिकायत प्रस्तुत करने से पहले, यह आवश्यक है कि प्रभावित व्यक्ति संबंधित एडीबी संचालन विभाग और/या आईएनआरएम के साथ काम करके समस्या को हल करने के लिए एक अच्छा विश्वास प्रयास करें। ऐसा करने के बाद ही, और अगर वे अभी भी असंतुष्ट हैं, तो क्या जवाबदेही तंत्र शिकायतकर्ता को समीक्षा के लिए योग्य मानेगा। शिकायत एडीबी के विकासशील सदस्य देशों की किसी भी आधिकारिक भाषा में प्रस्तुत की जा सकती है। एडीबी जवाबदेही तंत्र की जानकारी परियोजना जीआरएम परियोजना के हिस्से के रूप में प्रभावित समुदायों को वितरित की जाने वाली परियोजना-प्रासंगिक जानकारी में शामिल है।

45. पीएमयू और एएसयू साइट कार्यालय शिकायतकर्ता के संपर्क विवरण, शिकायत प्राप्त करने की तारीख, शिकायत की प्रकृति, सहमत सुधारात्मक कार्रवाई, की गई कार्रवाई की तारीख और उनके परिणाम सहित प्राप्त सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखेंगे। एएसयू साइट कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर भी रखा जाएगा। जीआरएम की लागत पीएमयू ऑपरेटिंग बजट द्वारा वित्तपोषित की जाएगी।

VIII. निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन

46. परियोजना प्रबंधन सहायता के लिए परामर्श फर्म के सामाजिक विकास और लिंग विशेषज्ञ के सहयोग से पीएमयू लिंग और स्वदेशी लोग विशेषज्ञ, समाप्ति के 30 दिनों के भीतर एडीबी को प्रत्येक अवधि के अर्धवार्षिक सामाजिक सुरक्षा उपायों की निगरानी रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। पहली अर्धवार्षिक सामाजिक सुरक्षा निगरानी रिपोर्ट ऋण प्रभावशीलता की तारीख से पहले 6 महीनों को कवर करेगी। अर्धवार्षिक सामाजिक सुरक्षा उपायों की निगरानी रिपोर्ट में विस्तार से बताया जाएगा कि कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण के मामले में स्वदेशी लोगों को परियोजना से कैसे लाभ होता है; आवासीय, उद्यमिता, और अन्य सुविधाएं और सेवाएं; कैरियर विकास कार्यक्रम और सेवाएं; और रोजगार। परियोजना के लिए डिजाइन और निगरानी ढांचे और लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन कार्य योजना में अनुसूचित जनजाति समूहों सहित महिलाओं और वंचित समूहों के लिए संकेतक और लक्ष्य शामिल हैं, जैसे कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण में नामांकन, और सतत शिक्षा कार्यक्रम, और कैरियर विकास की डिलीवरी कार्यक्रम और सेवाएं। एडीबी द्वारा समीक्षा के बाद, अर्धवार्षिक सामाजिक सुरक्षा उपायों की निगरानी रिपोर्ट एडीबी की वेबसाइट पर प्रकट की जाएगी।

XI. संस्थागत व्यवस्थाएं

47. असम सरकार का कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग (SEED) परियोजना की निष्पादन एजेंसी होगी, और एएसडीएम कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ASDM ने PMU की स्थापना की है, जो स्वदेशी लोगों के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के समन्वय और सुविधा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगा। पीएमयू में एक पूर्णकालिक लिंग और स्वदेशी लोगों के विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाएगा और परियोजना प्रबंधन सहायता के लिए परामर्श फर्म के सामाजिक विकास और लिंग विशेषज्ञ द्वारा समर्थित किया जाएगा। इसके अलावा, छात्र आउटरीच सहायता प्रदान करने के लिए एक अन्य परामर्श फर्म या गैर-सरकारी संगठन लगाया जाएगा। स्वदेशी लोग विशेषज्ञ और परामर्श फर्म के सामाजिक विकास और लिंग विशेषज्ञ SEED, ASDM और ASU, PMU कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य सलाहकारों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए परियोजना के अंतर्गत व्यस्त रहेंगे और कार्य योजना पर प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे।

X. बजट और वित्तपोषण

48. स्वदेशी लोगों के लिए कार्य योजना को लागू करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने और रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक बजट लगभग 1.0 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है जिसे परियोजना लागत में शामिल किया गया है। विवरण तालिका 5 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 5: स्वदेशी लोगों के लिए बजट योजना

कार्य	जिम्मेदारी	बजट (बजट का स्रोत)	आवंटन
एएसयू में अनुसूचित जनजाति आबादी सहित महिलाओं और वंचित समूहों के हित और नामांकन को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करना।	एएसयू, प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास के लिए परामर्श फर्म पीएमयू	एएसयू प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम विकास के लिए परामर्श फर्म (एडीबी ऋण)	10%
संभावित छात्रों के बीच जागरूकता में सुधार और उनके परिवार तक पहुंचने के लिए प्रचार और आउटरीच गतिविधियों के लिए एक योजना तैयार करना और संचालन करना, विशेष रूप से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति समुदायों में	पीएमयू, परियोजना प्रबंधन सहायता और आउटरीच समर्थन के लिए परामर्श फर्म एएसयू	आउटरीच समर्थन के लिए परामर्श फर्म (एडीबी ऋण)	20%
इसके छात्र सुविधा के माध्यम से भावी छात्रों और उनके परिवारों को छात्रवृत्ति और अन्य पर जानकारी और वित्तीय सहायता योजनाएं और कार्यक्रम का प्रसार करना ।	एएसयू, प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम विकास के लिए परामर्श फर्म, पीएमयू	एएसयू ऑपरेटिंग बजट (समकक्ष निधि)	15%
एएसयू की आवासीय सुविधाओं पर जानकारी का प्रसार सभी संभावित छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए और छात्रों, संकाय और कर्मचारियों के लिए तरजीही उपचार, जिनमे अनुसूचित जनजाति समूह भी शामिल हैं।	एएसयू, प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम विकास के लिए परामर्श फर्म, पीएमयू		
विकास और कैरियर विकास कार्यक्रमों और सेवाओं के सॉफ्ट और भाषा कौशल विकास कार्यक्रमों का वितरण करना, विशेष रूप से महिला छात्रों और वंचित पृष्ठभूमि के छात्र, जिनमें शामिल हैं अनुसूचित जनजाति समूह	एएसयू, कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास के लिए सलाहकार, कैरियर विकास सेवा विकास के लिए लेनदेन टीए सलाहकार	एएसयू परिचालन बजट, कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास के लिए सलाहकार, कैरियर विकास के लिए लेनदेन टीए सलाहकार (समकक्ष निधि, एडीबी ऋण, संलग्न टीए)	२०%

स्थानीय समुदायों के बीच, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन और पारंपरिक ट्रेडों में मौजूदा कौशल पर निर्माण और वितरण करना, अनुसूचित जनजाति समुदायों सहित।	एएसयू, कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास के लिए परामर्शदाता	एएसयू ऑपरेटिंग बजट, कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास के लिए सलाहकार (समकक्ष निधि, एडीबी ऋण)	20%
जीआरएम का संचालन, निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन, और प्रशिक्षण कार्यशालाओं का संगठन करना।	पीएमयू, परियोजना प्रबंधन समर्थन के लिए परामर्श फर्म	पीएमयू परिचालन बजट ($2.1 मिलियन), परियोजना प्रबंधन सहायता के लिए परामर्श फर्म (सामाजिक विकास और लिंग विशेषज्ञ) (एडीबी ऋण)	15%

एडीबी = एशियाई विकास बैंक, एएसयू = असम कौशल विश्वविद्यालय, जीआरएम = शिकायत निवारण तंत्र, पीएमयू = परियोजना प्रबंधन इकाई, टीए = तकनीकी सहायता।

स्रोत: एडीबी और असम सरकार।

परिशिष्ट 1: हितधारक परामर्श

चित्र 1: मंगलदोई में प्रस्तावित एएसयू परिसर स्थल के आसपास के निवासियों / ग्रामीणों के साथ चर्चा

चित्र 2: स्थानीय पंचायत के नेताओं के साथ मंगलदोई में बातचीत

चित्र 3: मंगलदोई में प्रस्तावित एएसयू परिसर स्थल के आसपास सामूहिक सैर के दौरान स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत में बहु-हितधारक

चित्र 4: दरांग जिला कलेक्टर की अध्यक्षता द्वारा बहु हितधारक परामर्श

चित्र 5: गुवाहाटी में एक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में महिला और पुरुष छात्रों के साथ फोकस समूह चर्चा

चित्र 6: गुवाहाटी में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पर अपने विचार साझा करता हुआ एक छात्र

चित्र 7: गुवाहाटी में प्लेसमेंट अधिकारियों और एक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के साथ चर्चा

चित्र 8: गुवाहाटी में नियुक्ति के अधिकारियों और एक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों के साथ चर्चा

परिशिष्ट 2: हितधारक परामर्श का विवरण

	हितधारक परामर्श	दिनांक
	सुश्री:मधुचंदा तालुकदार, असम सिविल सेवा (एसीएस) उप सचिव कौशल उद्यमिता विभाग, असम सरकार	11 नवंबर 2021
	श्री मृगेश एन बरुआ, एसीएस निदेशक सादा जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, असम सरकार	11 नवंबर 2020
	सुश्री शांता शर्मा प्रतिनिधि भारतीय उद्योग परिसंघ, गुवाहाटी	11 नवंबर 2020
	परामर्श दरांग जिले में बैठक श्री दिलीप कुमार बोरा जिला कलेक्टर दरांग श्री नबज्योति दास, श्री पंकज कुमार डेका, श्री कुमार सुरजीत बरुआ अतिरिक्त उपायुक्त, दरांग श्री गौरांग कुमार दास जिला श्रम अधिकारी, दरांग सुश्री माधुरी बोरा जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी श्री गोबिंद कैता प्रखंड विकास अधिकारी मंगलदोई सुश्री राजश्री अनिल महासचिव, होरिजन (गैर सरकारी संगठन) श्री नयन एस पाठक अंचल अधिकारी मंगलदोई सुश्री रेखा बिस्वास,अध्यक्ष ग्राम पंचायत	12 नवंबर 2020

	श्री गजेंद्र देसा पंचायत प्रधान	
	मंगलदोई में एएसयू परिसर स्थल के आसपास 14 निवासियों (8 महिलाएं, 6 पुरुष) के साथ परामर्श बैठक	12 नवंबर 2020
	फोकस समूह चर्चा 40 छात्रों (10 महिलाएं, 30 पुरुष) और 10 प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारियों (8 महिलाएं, 2 पुरुष), अजिताक्ष वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	11 नवंबर 2020
	फोकस समूह चर्चा 5 प्रशिक्षकों (4 महिलाएं, 1 पुरुष) और 20 छात्रों (12 महिलाएं, 8 पुरुष), फ्लाईवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	21 जनवरी 2021
	फोकस 15 छात्रों (10 महिलाएं, 5 पुरुष) और 10 प्रशिक्षकों (7 महिलाएं, 3 पुरुष), नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर, गुवाहाटी के साथ समूह चर्चा	21 जनवरी 2021
	श्री एंड्री फांगचू, तारावती विकास फाउंडेशन (गैर-सरकारी संगठन)	21 जनवरी 2021